

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2970
जिसका उत्तर 12 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

चेकडैम और नहरों का रख-रखाव

2970. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में मौजूदा चेकडैम और नहरों के उचित रखरखाव की कमी के कारण किसानों को प्रभावित करने वाले जल संकट से अवगत है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार का इस क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं में सुधार के लिए खेती के पानी की कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक नहरों और चेकडैमों के निर्माण का प्रस्ताव है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

श्री राज भूषण चौधरी

(क) से (ग): जल राज्य का विषय है और जल संसाधन परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण, निष्पादन और अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा स्वयं उनके अपने संसाधनों और प्राथमिकता के अनुसार किया जाता है। भारत सरकार की भूमिका इस मंत्रालय की चल रही योजनाओं के अंतर्गत कुछ अभिज्ञात परियोजनाओं के लिए एक प्रेरक के रूप में तकनीकी सहायता प्रदान करने और आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है। इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय जल आयोग द्वारा परियोजनाओं के जल संसाधनों का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन किया जाता है।

पुरुलिया, पश्चिम बंगाल में सिंचाई सुविधाओं में सुधार करने हेतु कृषि जल की कमी को पूरा करने के लिए वैकल्पिक नहरों और चैक बांधों का निर्माण अथवा मौजूदा चैक बांधों और नहरों के उचित रखरखाव में कमी के कारण जल संकट के संबंध में केन्द्रीय जल आयोग में कोई विशिष्ट सूचना अथवा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
